Kashmir has glorious traditions of secularism. Every effort must be made to nurture and strengthen the secular forces in the State. The meeting also reaffirmed the resolve of the people and their representatives to resolutely meet the challenge to the unity and integrity of the country. The meeting placed on record its appreciation of the outstanding work done by the security forces including the J & K Police in combating the terrorism in the State under very difficult and trying conditions, and extended its condolences to the families of all those members of the security forces, administration and civilians who have lost their precious lives in this conflagration.

The threat of militancy and terrorism can be met only by mobilising the will of the people at large. The meeting appealed to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh to stand united in these difficult times, to ensure return of peace and tranquility.

A large number of suggestions for dealing with various aspects of the political, economic and regional dimensions were made, including the external factors involved. It was decided that the political dialogue would be continued, so that the political activities in the State can be restored. The meeting called upon all misguided youth of the State to shun the self-defeating path of violence and rejoin the political mainstream in the nation building activities.

बाबरी मस्जिद में प्रवेश

578. श्री सुरेश कलमाडी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 1991 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "मुस्लिम नाट बारड बाई कोर्ट ऑर्डर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन मुसलमानों को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद में प्रवेश नहीं करने देते, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि विश्व हिन्दू परिषद तथा इसके समर्थकों ने विवादास्पद भूमि पर कब्जा कर लिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) प्रश्नगत समाचार की सरकार को जानकारी है रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद से संबंधित मामला काफी समय से न्यायालय के विचाराधीन है तथा मामले से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर न्यायालयों द्वारा कई आदेश जारी किए जा चुके हैं । इस समय मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में लम्बित है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में से एक आदेश में अधिग्रहण की गई भूमि का हस्तांतरण न करने की व्यवस्था है । उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिये हैं कि भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से संबंधित न्यायालय के आदेशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाएगा तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़ मामलों में, न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ।

Fire safety in buildings

579. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1311 given in the Rajya Sabha on the 11th September, 1991 and state:

(a) whether Government have no records of actual action taken in the matter by each of the State Governments;

(b) whether Union territory of Delhi has also not been strictly fol-